रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 100] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1998/चैत्र 9, 1920
No. 100] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1998/CHAITRA 9, 1920

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1998

सा. का. नि. 153 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं. आ. 169"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 1998

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 1998 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियों, जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्ति के संबंध में राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों हेतु केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

	राज्य	(रुपए लाखों में)
	(1)	(2)
1.	आंध्र प्रदेश	12411.50*
2.	अरुणाचल प्रदेश	557.00
3.	असम	3958.00
4.	बिहार	4112.00
5.	गोवा	85.00
6.	गुजरात	11048.00
7.	हरियाणा	1983.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2133.00
9.	जम्मू-कश्मीर	1559.00
10.	कर्नाटक	3312.00
11.	केरल	4385.00
12.	मध्य प्रदेश	4042.00
13.	महाराष्ट्र	5398.00
14.	मणिपुर	196.00
15.	मेघालय	221.00
16.	मिजोरम	100.00
17.	नागालैंड	135.00

	(1)	(2)
18.	उड़ीसा	4898.25*
19.	पंजाब	4286.00
20.	राजस्थान	14170.00
21.	सिक्किम	373.00
22.	तमिलनाडु	4697.00
23.	त्रिपुरा	356.00
24.	उत्तर प्रदेश	9902.00
25.	पश्चिमी बंगाल	5129.25*

*इसके अन्तर्गत 1998-1999 के लिए आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल वित्तीय राहत निधि हेतु क्रमशः 2582.50 लाख रुपए, 1019.25 लाख रुपए और 1067.25 लाख रुपए का केंद्रीय अंश का अग्रिम निर्मोचन है।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी।

परन्तु यह और कि यदि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो अविशेष राज्य के वित्तीय राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप पैरा (1) के अधीन संदेय राशियों में से कोई राशि, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1997 के पैरा 3 के उप पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के० आर० नारायणन्,
राष्ट्रपति

[फा० सं० 19(3)/98-वि०-I]

रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1998

G. S. R. 153 (E).—The following Order made by the President is published for general information:–

"C.O. 169"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 1998

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1998.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief in connection with natural calamities in the States:—

	State	(Rupees in lakhs)
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	12411.50*
2.	Arunachal Pradesh	557.00
3.	Assam	3958.00
4.	Bihar	4112.00
5.	Goa	85.00
6.	Gujarat	11048.00
7.	Haryana	1983.00
8.	Himachal Pradesh	2133.00
9.	Jammu and Kashmir	1559.00
10.	Karnataka	3312.00
11.	Kerala	4385.00
12.	Madhya Pradesh	4042.00
13.	Maharashtra	5398.00
14.	Manipur	196.00
15.	Meghalaya	221.00
16.	Mizoram	100.00
17.	Nagaland	135.00
18.	Orissa	4898.25*
19.	Punjab	4286.00
20.	Rajasthan	14170.00
21.	Sikkim	373.00
22.	Tamil Nadu	4697.00
23.	Tripura	356.00
24.	Uttar Pradesh	9902.00
25.	West Bengal	5129.25*

*Includes advance release of Centre's share of Rs. 2582.50 lakh, Rs. 1019.25 lakh and Rs. 1067.25 lakh towards Calamity Relief Fund of Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal, respectively, for 1998–99.

Provided that the sums specified above shall be expanded in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997 on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in purauance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1997.

K. R. NARAYANAN,
President.

[F.No. 19 (3)/98-V.I]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998